जनसत्ता

वार्ता का संदेश

पाकिस्तान की तरफ से फिर यह संदेश आया है कि वह भारत के साथ हर मुद्दे पर सकारात्मक बात करने को तैयार है। अगर वह भारत के साथ वाकई गंभीरता से वार्ता की मेज पर आना चाहता है तो दोनों देशों के लिए इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है! लेकिन अब तक का इतिहास तो यही बता रहा है कि ऐसा कभी हो नहीं पाया। जब-जब भारत ने अपनी ओर से शांति की पहल की, बदले में उसे करगिल जैसे दंश मिले। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जोरदार जीत और दूसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फोन पर बधाई दी और भारत से अच्छे रिश्ते व सहयोग की उम्मीद जताई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान से साफ कह दिया कि पहले उनका देश भारत के खिलाफ आतंकवाद खत्म करे, तभी किसी तरह की वार्ता की कोई सूरत बन सकती है। भारत के इस जवाब को कूटनीतिक अर्थों में भी काफी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रधानमंत्री का जवाब बता रहा है कि भारत अपनी तरफ से हमेशा और हर मुद्दे पर बात करने को तैयार रहा है, लेकिन पाकिस्तान मौका पाते ही ऐसे मौकों को पटरी से उतार देता है।

इस साल फरवरी में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान से फोन पर बात की। यों तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक तरह का तनाव पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन पुलवामा के आतंकी हमले ने तो वार्ता की संभावनाओं पर पानी फेर डाला। इससे तो पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सख्त कदम उठाया और पाकिस्तान के बालाकोट में चल रहे आतंकी शिविरों पर बम बरसा कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई का जो सख्त संदेश गया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज वार्ता की मेज पर आने की बातें कर रहा है। हालांकि इमरान खान ने पिछले साल सत्ता संभालने के बाद ही कहा था कि वे पड़ोसी देश भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं और भारत एक कदम बढ़ाएगा तो वे दो कदम बढ़ाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत को लेकर इमरान खान वाकई गंभीर हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। लेकिन सवाल है आखिर मामला फंस कहां जाता है जिससे शांति की दिशा में कदम बढ़ नहीं पाते! यह इमरान खान को सोचना चाहिए।

पिछले कुछ समय में इमरान खान एक-दो मौकों पर यह कह भी चुके हैं कि कश्मीर सहित सभी विवादित मुद्दों को केवल मोदी सुलझा सकते हैं। इस बयान की वजह से इमरान को अपने ही सांसदों की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। लेकिन इतना साफ है कि इमरान ने सकारात्मक भाव दिखाया है, भले यह भारत की कूटनीति की वजह से हो, मोदी के प्रभाव और सख्त रुख की वजह हो या फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव में हो। भारत तो शुरू से ही 'पड़ोसी प्रथम' की नीति पर चलने की बात कहता आया है और भारत ने अपनी ओर से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के प्रयास भी किए। लेकिन पुलवामा, उड़ी और पठानकोट जैसे आतंकी हमले इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में भारी फर्क है। जब तक वह अपने इस दोहरे चरित्र को नहीं छोड़ेगा तब तक बातचीत के प्रयास सफल नहीं हो सकते।

केन का जीवन

दुनिया की ज्यादातर नदियां अपने तटवर्ती इलाकों के लिए जीवनदायिनी रही हैं। सभ्यताओं के विकास में नदियों का क्या योगदान रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि जो मानव सभ्यताएं नदियों से जीवन पाती रही हैं, उन्हीं की वजह से आज बहुत सारी नदियों का अस्तित्व मुश्किल में है। बुंदेलखंड के इलाके में बहने वाली केन नदी आज जिस संकट से दो-चार है, उसका हल वक्त रहते निकाला जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम और हमारी सरकारें तब तक किसी समस्या पर गौर करना जरूरी नहीं समझतीं, जब तक पानी नाक के ऊपर न बहने लगे। जो केन नदी समूचे बुंदेलखंड इलाके की जीवन-रेखा के तौर पर देखी-जानी जाती थी, आज हालत यह है कि उसकी धारा सूखने की राह पर है और उसे अकाल मौत से बचाने के लिए अब जाकर एक ओर सरकारी तंत्र थोड़ा सक्रिय होता दिख रहा है तो दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर भी कुछ पहलकदमी हुई है। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की कवायदें वक्त पर शुरू नहीं हो पातीं।

गौरतलब है कि केन के जलप्रवाह में काफी कमी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नदी के तटीय इलाकों की निगरानी शुरू कर दी है। हालत यह है कि नदी के किनारे हथियारों से लैस पुलिसकर्मी खड़े होकर दूरबीनों के जरिए इस बात पर नजर रख रहे हैं कि किसी गतिविधि की वजह से केन के जलप्रवाह में बाधा तो नहीं आ रही है। खासतौर पर अवैध खनन कारोबारी दूरदराज के दुर्गम इलाकों में नदी की धारा को रोक कर बालू का खनन करने लगते हैं। इस वजह से शहरी इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए नदी में बने 'इन-टेक-वेल' तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस केन की हालत क्या हो चुकी है, जिसके पानी पर बड़ी तादाद में लोगों की निर्भरता है। गर्मी के मौसम में पहले ही इस नदी में जलप्रवाह मामूली रह जाता है। ऐसे में भी अवैध खनन से लेकर तटीय ग्रामीण इलाकों के लोग नदी के किनारे सब्जी आदि की खेती की सिंचाई के लिए प्रवाह रोकते हैं। जाहिर है, इसका सीधा असर जरूरतमंद क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए पानी के संग्रह पर असर पड़ता है।

यानी कभी जिस नदी के पानी से जिला मुख्यालय के अलावा करीब पचास गांवों के किसान अपनी प्यास बुझाते थे, वह केन आज सूखती जा रही है। इस नदी की गिनती सबसे स्वच्छ नदियों में की जाती थी, जिसके पानी का उपयोग लोग पेयजल के रूप में करते रहे हैं। नदी और इसके तट पचास से ज्यादा प्रकार के पेड़, वनस्पति और जीव-जंतु से समृद्ध रहे हैं। लेकिन आज केन के तट पर बसे कई शहरों का गंदा पानी सीधे नदी में जा रहा है। यही नहीं, इन शहरों के चिकित्सा और विषैले अपशिष्ट भी नदी में बहा दिए जाते हैं। इसके अलावा, बालू माफियाओं के अवैध खनन से नदी की दशा और दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। यही वजह है कि केन को बचाने के लिए किसानों ने भी अपने स्तर पर आंदोलन छेड़ा था। अब इस मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवियों ने भी पहल की है और इसके मद्देनजर सोशल मीडिया पर 'मैं भी भगीरथ' नाम से मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए केन नदी को बचाने के मकसद से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। वक्त रहते अगर केन को पहले के स्वरूप में वापस लाया जा सके तो यह समूचे इलाके के हित में होगा, अन्यथा इसका खमियाजा समाज को ही भुगतना पड़ेगा।

कल्पमेधा

केवल दो चीजें अनंत हैं, यह ब्रह्मांड और मानवीय मूर्खता। ब्रह्मांड के बारे में मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता।

-अल्बर्ट आइंस्टीन

रेत खनन और चुनौतियां

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

पूरे देश में अवैध रेत खनन का कारोबार माफिया और आपराधिक तत्त्वों के हाथ में है। जो ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हैं उन पर रेत से भरे ट्रक, ट्रैक्टर चढ़ा देना, हत्या कर देना, उनका तबादला करवा देना माफिया के लिए आम है। माफिया में ऐसी हिम्मत उनके राजनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों व अपराधी तत्त्वों के साथ जगजाहिर संबंधों से आती है।

सीमेंट और कंकरीट के निर्माण कार्यों में रेत का उपयोग अपरिहार्य है। आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवास, स्कूल, अस्पताल या सड़क हों या पेयजल भंडारण से जुड़ी जरूरतें सभी के निर्माण में रेत, सीमेंट, कंकरीट आदि की मांग तेजी से बढ़ी है। रेत में भी प्राथमिकता में मांग नदियों से निकलने वाली रेत की है। इसलिए भारत सहित दुनिया भर में ही नदियों से रेत खनन अत्यधिक होने लगा है। गैर कानूनी रेत खनन का कारोबार पूरे देश में ही आपराधिक हिंसक प्रवृत्तियों के साथ जड़ें जमा चुका है। गुजरात में साबरमती नदी में रेत का इतना अवैध खनन होता रहा है कि अमदाबाद, साबरकांठा, गांधीनगर जिलों में इन पर निगाह रखने के लिए 2018 में ड्रोन से निगरानी तक की गई। यह स्थिति तब है जब 2016 के बाद साबरमती नदी में गांधीनगर और अमदाबाद के बीच रेत खनन पूरी तरह से रोक दिया गया था और इस बीच के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने स्वीकार किया था कि राज्य में अवैध खनन बहुत गंभीर समस्या है। अन्य राज्य भी इस समस्या से बचे नहीं हैं। राज्य विधानसभाओं में भी इस पर चर्चा होती है, लेकिन अवैध रेत खनन नहीं हो रहा है, ऐसा न सत्तारूढ़ दल कहता है न विपक्ष।

रेत खनन से नदियों की पारिस्थितिकीय प्रणालियों के साथ-साथ तटीय क्षरण, नदी तलहटियों की भू-आकृतीय संरचनाओं में बदलाव, मछलियों, घड़ियालों, कछुओं जैसे जलजीवों के आवागमन व प्रजनन क्षेत्रों में अवरोध और आत्मरक्षा के लिए उनके छुपने के क्षेत्रों पर संकट भी आ जाता है। गंगा की ही बात लें तो वैज्ञानिकों ने ही यह पुष्ट किया है कि रेत खनन से ऐसे कछुए, जिन्हें एक बार सफाई के लिए गंगा में डाला गया था, अब लगभग समाप्त हो गए हैं। ये कचरे को नष्ट करने में मददगार होते थे। नदियों की वनस्पतियां भी रेत खनन से प्रभावित होती हैं। रेत कई तरह के प्रदूषण से बचाने में मददगार होती है। इससे पानी की गुणवत्ता ठीक रखने में भी मदद मिलती है।

नदी तलहटियों से रेत खनन से नदियों में जल प्रवाह की दशा व गति पर भी असर पड़ता है। आसपास की खेती भी इससे प्रभावित होती है। नदियों व पर्यावरण के लिए रेत के महत्त्व को स्वीकारते हुए अदालतों व सरकारी मानकों ने भी पर्यावरण हित में रेत खनन को नियमित व कई जगहों पर प्रतिबंधित किया है। निर्देशों में साफ कहा गया है कि पुलों और आवासीय बस्तियों के पास रेत खनन न हो। किंतु खनन वहां भी होता है। हद तो यह है कि घोषित ईको सेंसटिव व वन क्षेत्रों में भी अवैध रेत खनन हो रहा है। कुल मिला कर तथ्य यह है कि बिना प्रशासन की मदद के अवैध खनन नहीं हो सकता है।

इस बीच नदियों में रेत खनन के मामले को समग्रता में समझने का एक अवसर राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) का एक हालिया निर्देश देता है। अप्रैल, 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार पर अवैध रेत खनन रोकने में असमर्थ रहने पर कुछ निर्देशों के साथ सौ करोड़ रुपए का अंतरिम दंड भी लगाया गया था। राज्य के मुख्य सचिव को अनियमित रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने के आदेशों के साथ-साथ यह भी चेताया गया था कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का ट्रस्टी है व उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी है। निस्संदेह एनजीटी यह भी जानता है कि रेत खनन का अवैध कारोबार पूरे देश में आपराधिक तत्त्वों और माफियाओं के कब्जे में है और उसके पहले के निर्देश भी विभिन्न राज्यों में दिखावे के लिए ही स्वीकारे जाते हैं।

रेत की मांग के मुकाबले आपूर्ति में भारी कमी बनी हुई है। भारत में ही मांग को पूरा करने के लिए कुछ हद तक अवैध रेत खनन को कम करने के लिए कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे राज्य लाखों टन रेत आयात कर उपभोक्ता व उद्योगों को दे भी रहे हैं। निजी आयातकों के लिए यह लाभ का सौदा भी हो रहा है। 2017 से मलेशिया से ऐसा आयात जोर पकड़ रहा है। राज्य अपने यहां नदियों की रेत दूसरे राज्यों से मंगा कर बेच रहे हैं। इसके अलावा, रेत की कमी पूरी करने के लिए स्टोन क्रैशरों से राज्यों के भीतर भी पत्थरों-चट्टानों से रेत निर्माण की मंजूरी दी जा रही है। नतीजतन, कई जगहों पर लगभग पूरी की पूरी पहाड़ियों को मटियामेट कर

दिया है। अवैध रेत खनन की संभावनाएं तब भी बढ़ जाती हैं जब स्टोन क्रैशर भी नदियों के पास लगे हों। कई जगहों पर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने इनसे होने वाले वायु प्रदूषण, जल भंडारों व पारिस्थितिकीय नुकसानों पर विरोध भी जताया है। यह भी कहा जा सकता है कि जब पूरे समुद्रों में रेत है, रेगिस्तानों में रेत है तो फिर भारत में रेत के मशीनी उत्पादन की आवश्यकता क्यों हो जाती है। समुद्र की रेत लवणीय होने के कारण और रेगिस्तान की रेत गोल होने व कम खुरदुरी होने के कारण निर्माण के लिए आदर्श नहीं मानी जाती है।

यदि रेत खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में पहले से ही यह अध्ययन न किया गया हो कि वहां से कितनी रेत बजरी पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाए बिना निकाली जा सकती है तो वैध खनन से भी पर्यावरणीय हानि हो सकती है। वैज्ञानिक अध्ययनों और आंकड़ों की कमी के कारण रेत खनन से हुए कुप्रभावों का सही पता नहीं चल पाता है। जैसा कि आदेश में भी कहा गया है कि यदि खनन से कोई हानि हुई है तो उसकी भरपाई की जाए तो निस्संदेह खनन के बाद वाले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भी जरूरी हो गए हैं, क्योंकि तभी तो आप भरपाई की बात सोच सकते हो। नदियों में खनन का तो अब तक का इतिहास यही रहा है कि जितने खनन की अनुमति ली जाती है उससे कई गुना ज्यादा का खनन होता है। बाद के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से ही पता चल पाएगा कि जितने खनिज, उपखनिज को निकाला जाना है व जिस जगह से निकाला जाना है, जिन तरीकों से और जिन मशीनों से निकाला जाना है, उनसे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में किनारों के भूजल भंडारण पर होने वाला अंतर, किनारों का कटाव, नए भूस्खलन, भूधंसाव, भूक्षरण के संभावित क्षेत्रों का भी उल्लेख होता है।

दरअसल, विरोध रेत के अवैध खनन को लेकर है। लेकिन जिन पहलुओं को एनजीटी ने छुआ है वे वैध खनन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। पर्यावरण प्रभाव और ट्रस्टीशिप संबंधी चिंता वैध और अवैध दोनों मामलों में प्रासंगिक है। वैध खनन पर तो निगरानी रखनी और भी आवश्यक है, क्योंकि भारी मात्रा में अवैध खनन वैध खनन की आड़ में ही होता है। स्वीकृत गहराइयों से दुगनी-तिगुनी गहराइयों तक पहुंच कर रेत खनन किया जाता है। जिन चिह्नित क्षेत्रों के लिए रेत खनन पट्टा होता है उनसे बाहर जाकर भी खनन होता है। ढुलाई वाहन पारपत्र पर दर्शाए गए माल से दुगना-तिगुना माल लेकर बेरोकटोक बाहर निकाले जाते हैं। ज्यादातर जगहों पर तो इन ढुलाई वाहनों पर नंबर प्लेट भी नहीं होतीं। पूरे देश में अवैध रेत खनन का कारोबार माफिया और आपराधिक तत्त्वों के हाथ में है। जो ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हैं उन पर रेत से भरे ट्रक, ट्रैक्टर चढ़ा देना, हत्या कर देना, उनका तबादला करवा देना माफिया के लिए आम है। माफिया में ऐसी हिम्मत उनके राजनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों व अपराधी तत्त्वों के साथ जगजाहिर संबंधों से आती है। इसीलिए अवैध रेत खनन पर शिकंजा कस पाना संभव नहीं लग रहा।

बितले चइतवा हो रामा

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

बदलती ऋतुओं के साथ धरती अपना परिधान बदलती है तो हमारी संगीत शैलियों के भी स्वर, शब्द, भाव बदलते जाते हैं। ऋतुओं का चक्र ही इस कृषि प्रधान देश का सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक जीवन संचालित करता है। चैत्र से वर्ष का प्रारंभ होने से कुछ पहले ही फागुन का उल्लास शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोक संगीत सभी के स्वरों में डूबने-उतराने लगता है। फागुन के मदमाते उल्लास में डूबी ब्रजभूमि राधा-कृष्ण की अभिसारमय होली का रसिया आख्यान गुनगुनाती है तो अवध में राम-लक्ष्मण-सीता की स्वर्ण पिचकारियों से फूटते इंद्रधनुषी रंगों को राग काफी और पीलू के परंपरागत स्वरों में गाई होरी में पिरो दिया जाता है। गिरिजा देवी, पंडित छन्नूलाल मिश्र आदि की बनारसी शैली में पगी होरी में नायिका नायक से अनुनय विनय करती रह जाती है कि उसकी चुनरी रंग में सराबोर न करे, उधर पंडित जसराज के गूंजते हुए स्वर में राधा लालगोपाल से 'अंखियन में रंग न डारने' का आग्रह करती है। छन्नूलाल मिश्र को तो होली खेलते 'ना साजन दिखें ना गोरी, दिखें तो भूत पिशाच और अघोरी', वह भी श्मशान में 'मसाने की होरी' खेलते हुए। लेकिन मरघट में उपजा यह दर्शन भी होली के उल्लास को नहीं मार पाता। अभिसार, मस्ती और ठिठोली के स्वर फूटते हैं खेतों से खलिहान में पहुंचने को आतुर सुनहरी गेहूं की बालियों को देखकर। तैयार फसल की समृद्धि से उद्वेलित उमंग की मशाल पर भला 'मसाने की होरी' की राख कैसे छा सकती है!

फसल का यह चक्र पूरा होते ही 'चइत' या चैत्र आ जाता है। धन-धान्य खेतों से घर तक भगवत्कृपा के बिना कैसे पहुंचता! इसलिए कृतज्ञ गृहस्थ चैत्र में राम जन्मोत्सव मनाते हुए गीतों की हर पंक्ति में 'हे रामा' शब्द पिरो देता है। 'हे रामा' से अलंकृत चइता ज्ञान योग की तरफ झुका हुआ पुरुष होता है। लेकिन चैती श्रृंगार प्रधान होती है- नारी हृदय की कोमलता में भीगी हुई। भोर की मद्धिम बयार में अलसती नायिका कोयल की कूक सुनती है तो चैती के कोमल स्वर उसके होठों पर आ जाते हैं- 'चैत मासे बोले रे कोयलिया हे रामा, मोरे अंगनवां।' गिरिजा देवी उसके अंतर में पैठ कर गाती हैं 'चैत मासे चुनरी रंग बे हो रामा, पिया घर अइहें'। बेला-चमेली की सुगंध में डूबे अभिसार के क्षणों की स्मृति नायिका के कपोलों को रक्ताभ कर देती है। माथे की 'हेराई हुई' बिंदिया वह कोठे पर खोजती है, अटरिया पर खोजती है, बस वहां ढूंढ़ने में लजा जाती है जहां उसके मिल जाने की संभावना है। पर श्रृंगार और अभिसार का ही दूसरा पहलू वियोग है।

रामजन्म से उल्लसित चैता और प्रिय के सान्निध्य में हुलसती चैती, दोनों जल्दी ही खेत-खलिहान के निष्ठुर सत्य से जूझेंगे। धीरे-धीरे चैत्र की बयार उग्र होने लगती है। फसल कटने के बाद सूने पड़े खेतों में धूल के बवंडर उठना शुरू हो जाते हैं। पच्छिम से आई 'अन्धियरिया' आम के पेड़ों पर झूलते टिकोरों को झकझोर कर बेरहमी से धरती पर पटकने लगती है। आतंकित फगुनिया बयार दो एक महीने में लौटती है तो अपने सीने में सूरज की धधक लेकर, काल बैसाखी का क्रुद्ध मुखौटा पहन कर। जेठ-बैसाख के महीनों में धरती को सूरज की तपन बेसुध कर देगी। खेतों का ममतामय आंचल शुष्क हवाओं में सूख कर उसके सीने को पत्थर की तरह जकड़ लेगा। अगली फसल की तैयारी तभी शुरू होगी जब इंद्र के दरबार में फिर से बादल के गायन और चपला के नृत्य का वार्षिक आयोजन होगा।

दुनिया मेरे आगे

श्रृंगार के ऊपर पेट की भूख भारी पड़ती है। अभिसार के क्षणों की याद की पोटली सिर पर लादे चैती का रसिया नायक फिर से कलकत्ते में रिक्शा खींचने, धनबाद की कोयला खदानों की आंत में घुसी चट्टानें तोड़ने और सुदूर प्रांतों के कारखानों में अपने खून-पसीने को चांदी के सिक्कों में बदलने की मुहिम पर निकल पड़ता है। उधर चैत्र के महीने में चुनरी मंगाने वाली नायिका के स्वर की खनक करुणा में गोते खाने लगती है। निष्ठुर सच्चाइयां सामने आती हैं तो चैती पहाड़ी राग के कोमल स्वरों में पूछ उठती है- 'अब सैंया का करे अइहें हो रामा, बितले चईतवा।'

इस बार धरती का परिधान दो-तीन महीनों के बाद बदलेगा जब सावन की घटाओं पर आरूढ़ होकर खमाज ठाट के मनमोहक स्वरों में सजी हुई कजरी आएगी। वियोगदग्ध चइती की जगह जब कजरी, सावन और झूला के गीत लेंगे तो सावन के झूलों में राधाकृष्ण और शंकर-पार्वती के संग हमारी नायिका और नायक भी झूलेंगे। चिढ़ाती हुई भौजाई पूछेगी- 'कैसे खेलन जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी।'

खेती किसानी का चक्र फिर घूमेगा। धान के खेतों में समृद्धि का बीज बोने के लिए ही सही, प्रिय के आने के दिन फिर लौटेंगे। लेकिन होरी, चइता और कजरी के बीच के इस लंबे अंतराल में चैती के करुण स्वरों को धूल उडाती हवाओं के बीच कई महीनों तक गूंजते रहने से कौन रोक सकेगा।

झुलसती संवेदनाएं

कोई देश विकास के ग्राफ पर कितना भी ऊपर जा रहा हो, उसका वास्तविक विकास इस बात से तय होता है कि वहां शासन और समाज व्यवस्था की प्राथमिकताएं क्या हैं। सुरक्षा और संवेदनशीलता के मामले में उसका कोष कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। हमारे देश में समय-समय पर बच्चों के साथ हादसे होते रहे हैं। लगभग बीस,-बाईस साल पहले बच्चों से भरी एक स्कूल बस यमुना नदी में गिर गई थी। बहुत से बच्चे पानी में डूब कर मर गए थे। इसमें स्कूल प्रशासन से लेकर बस ड्राइवर तक किसकी कितनी जिम्मेदारी थी, इस प्रश्न से अलग एक बड़ा प्रश्न यह उभरा था कि जिन अभिभावकों के घर उस दुर्घटना की वजह से सूने हो गए, उनके दुख को व्यवस्था की सफलता के लिए चुनौती क्यों नहीं माना गया क्योंकि साल-दर-साल देश भर में बच्चों के साथ हादसों का सिलसिला चलता रहा। इनमें लड़कियों के साथ हुए कुकर्मों और बलात्कारों को गिनवाने की जरूरत नहीं है पर व्यवस्था की प्राथमिकताओं में देश के बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा कहीं नजर नहीं आता।

सूरत में घटी ताजा दुर्घटना में बीस से अधिक छात्रों की मौत अखबारों की एक खबर बन कर रह गई लेकिन जिनके घरों के नौनिहाल इस अग्निकांड में स्वाहा हुए हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। इन माता-पिता की टीस व्यवस्था के कलेजे में हलचल क्यों नहीं मचा पाती? देश का भविष्य देश के बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है, इस सच्चाई के प्रति लापरवाह व्यवस्था में कभी इमारतों के अवैध निर्माण, कभी यातायात नियमों की अनदेखी, कभी स्कूल प्रशासन की लापरवाही की बलिवेदी पर बच्चे होम हो रहे हैं।

कड़ी दंड व्यवस्था के अभाव में बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे निष्कंटक जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसी तरह के सैकड़ों सवाल हैं जो बच्चों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा से जुड़े हैं। क्या ये सवाल देश के विकास से जुड़े बड़े प्रश्नों में शामिल होंगे? क्या देश की तरक्की करने से पहले देश के बच्चों को एक सुरक्षित, संवेदनशील और स्वस्थ वातावरण देना सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? यदि ऐसा नहीं है तो कैसा विकास? कैसी सफलता? कैसी खुशी?

● *सुमन शर्मा, रोहिणी, नई दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

परिवार के बगैर

कांग्रेस को करारी हार के बाद खुद में व्यापक बदलाव के लिए कमर कसनी होगी। यह बदलाव आत्ममंथन से ही संभव होगा, न कि दरबारी संस्कृति का परिचय देने से। जरूरी केवल यह नहीं कि गांधी परिवार इस संस्कृति में रचे-बसे लोगों को किनारे कर पार्टी को ईमानदारी से आत्ममंथन करने का मौका दे, बल्कि उससे जो हासिल हो उसे स्वीकार भी करे।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का काम नहीं चल पाता, लेकिन सच यह भी है कि परिवार के प्रभुत्व के चलते जनाधार वाले सक्षम नेता एक दायरे से ऊपर नहीं उठ पाते। कई बार तो उन्हें जानबूझ कर आगे नहीं आने दिया जाता। गांधी परिवार को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष के साथ ही उसका सकारात्मक होना आवश्यक है।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

खतरे की फसल

आम तौर पर भारत में दो फसलों यानी कपास और बैंगन को बीटी फसल के तौर पर जाना जाता है। बीटी का पूरा नाम 'बैसिलस थिरूजेनोसिस' है। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है, जिसे बीटी से निकाल कर बैंगन या कपास की कोशिका में दाखिल करा दिया जाता है। जीन संवर्धित फसल का मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता पर भयावह असर पड़ता है। अभी तक देश में सिर्फ बीटी कपास के उत्पादन की अनुमति है। बीटी बैंगन और इसके पौधे की कोशिकाओं में खास तरह का जहर पैदा करने वाला जीन होता है। इसी कारण सामान्य बैंगन में लगने वाले कीट इसमें नहीं लग पाते। जांच से पता चलता है कि बीटी बैंगन खाने वाले चूहे के फेफड़ों में सूजन, अमाशय में रक्त स्राव, उनकी संतानों की मृत्यु दर में वृद्धि जैसे बुरे प्रभाव दिखे हैं।

जीन संवर्धित फसल स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। इन बीजों से उगी फसलें और उनसे बनी खाद्य वस्तुओं से अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे विषाक्तता, एलर्जी और प्रतिरक्षण आदि पैदा होती हैं। प्रकृति और किसानों ने हजारों साल में हजारों किस्म के बैंगन विकसित किए हैं, वह सारा खजाना जीएम बैंगन के फैलने से खत्म हो सकता है। साथ ही, इसके औषधीय गुण भी समाप्त हो सकते हैं। जीएम फसलों को उत्पादित करने में कम कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है और शोध से पता चलता है कि सत्तर प्रतिशत कीटाणु इनके प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में तो ये फसलें किसानों के लिए किफायती हैं, लेकिन इनका उपयोग करने वाली जनता के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हैं। लिहाजा, इन्हें बढ़ावा देने के बजाय इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना ही उचित होगा।

● *दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

विश्वकप की उम्मीद

तीस मई से क्रिकेट विश्व कप शुरू हो रहा है। जब कोई टीम खेल के मैदान में उतरती है तो वह जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देती है। खेल में हार-जीत भी चलती रहती है। भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ टीमों में से एक मानी जाती है। विराट-सेना बहुत मजबूत है, लेकिन अगर यह दबाव मुक्त होकर मैदान में उतरेगी तो 2019 का क्रिकेट शत प्रतिशत भारत का होगा। बल्लेबाजी के महारथी विराट कोहली, शिखर धवन तथा रोहित शर्मा और गेंदबाजी के सरताज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह से उम्मीद है कि ये टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। पहली बार विश्व कप खेलने जा रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और केदार जाधव से आशा है कि वे शानदार प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्वकप में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर से डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ की टीम में वापसी की है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। कंगारुओं से निपटने के लिए भारतीय टीम को समझदारी से खेलना होगा।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

नई दिल्ली